<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया</u> :–

30 अक्टूबर, 2017

भुगत रहा है देश!

<u>8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी मनाएगी 'काला दिवस' – देश के हर जिले और राज्य मुख्यालय में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन</u>

<u>नोटबंदी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला– है 'मोदी निर्मित आपदा'</u>

<u>नोटबंदी और जीएसटी की दोहरी मार ने किया व्यापार ठप्प, खत्म हुई नौकरियां</u>

नोटबंदी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी इसके दुष्प्रभावों के शिकंजे से नहीं निकल पाई है। भुगत रहा है देश। कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नोटबंदी की भयंकर भूल की पहली सालगिरह पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने और इस दिन देश में 'काला दिवस' मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश के हर जिले और राज्य मुख्यालय में सड़कों पर उतरकर लोगों के कष्ट, पीड़ा व रोष को प्रदर्शित करेंगे। दुख तो इस बात का है कि सत्ता के नशे में चूर और आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे, श्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार भारत की अर्थव्यवस्था पर हुई 'सर्जिकल स्ट्राईक' का जश्न मना रही है। इस देश की जनता भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था को तार–तार करने वाले नोटबंदी के भयावह फरमान **ने प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में मुहम्मद बिन तुगलक** की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे **'सुनियोजित लूट और लोगों की जेब पर डाका'** की संज्ञा दी।

<u>केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता को निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने होंगे :–</u>

1- **<u>काला धन आखिर कहां गया?</u>**

आरबीआई की मानें तो 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी के समय चलन में 15.44 लाख करोड़ रु. में से 15.28 लाख करोड़ रु. वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है कि केवल 16000 करोड़ रु. अब तक वापस नहीं आए।

इसके विपरीत प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री जी ने दावा किया था कि नोटबंदी के चलते 3 से 5 लाख करोड़ रु. का काला धन जमा ही नहीं कराया जाएगा। **10 दिसंबर, 2016 को**

अटॉर्नी जनरल, श्री मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ''सरकार को 15 लाख करोड़ रु. में से 10 या 11 लाख करोड़ रु. का अनुमान है''।

<u>क्या मोदी जी बताएंगे कि जब सारा धन वापस बैंकों में जमा करा दिया गया, तो आखिर कालाधन गया कहां?</u>

2- **<u>'जाली करेंसी' कहां है? क्या यह भी एक 'जुमला' है?</u>**

प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि नोटबंदी का असली कारण जाली करेंसी का पता लगाना था। **यहां तक वित्त मंत्रालय ने भी दिनांक 8 नवंबर, 2016 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि नोटबंदी जाली करेंसी पकड़ने के लिए की गई थी।**

आरबीआई रिपोर्ट ने इस दावे को भी खोखला साबित कर दिया। वापस आए 15.28 लाख करोड़ नोटों में से केवल 41 करोड़ करेंसी नोट ही जाली पाए गए, यानि केवल 0.0013 प्रतिशत। जब 99.998 प्रतिशत करेंसी असली है, तो प्रधानमंत्री जी का पूरा दावा झूठा साबित हो जाता है।

500 रु./2000 रु. के नए नोटों में भी जाली करेंसी पकड़ी जा चुकी हे। एक मामले में बच्चे 2000 रु. के नए नोटों की फोटोकॉपी करके उन्हें चलाते हुए पकड़े गए।

3- **<u>क्या आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगी?</u>**

प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का एक कारण और दिया था कि इसका लक्ष्य आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाना था। आंकड़े इस दावे को भी झूठा साबित कर देते हैं। नोटबंदी के बाद अकेले जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद की 50 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें सेना के 80 जवान शहीद हुए और 51 नागरिक मारे गए।

नोटबंदी के बाद 17 बड़े नक्सली हमले हुए हैं, जिनमें 69 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 86 नागरिक मारे गए। ये आंकड़े साफ करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दावों में कितनी सच्चाई है।

4- **<u>'नई करेंसी' के नोट छापने का खर्चा 'बचत' से बहुत ज्यादा – नोटबंदी बनी एक तुगलकी भूल</u>**

आरबीआई ने बताया कि 16000 करोड़ रु. वापस बैंकों में नहीं आए। आरबीआई ने यह भी बताया कि नए नोटों की प्रिंटिंग/लॉजिस्टिक्स में 25,391 करोड़ रु. का खर्च आया। क्या मोदी जी 16000 करोड़ रु. बचाने के लिए 25,391 करोड़ रु. खर्च करने का गणित समझा पाएंगे?

5- **<u>क्या भारत 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' की ओर बढा?</u>**

प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का आखिरी कारण डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना बताया था। लेकिन उनका यह तर्क भी निराधार साबित हो गया। नवंबर, 2016 (नोटबंदी से पहले) में

हमारी अर्थव्यवस्था में 94 लाख करोड़ रु. का डिजिटल लेन–देन होता था। नोटबंदी के बाद जुलाई, 2017 में 104 लाख करोड़ रु. का डिजिटल लेन–देन हुआ। यानि नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन–देन में केवल 10 लाख करोड़ रु. का ही उछाल आया।

सच्चाई यह है कि डिजिटल लेन–देन में सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी कांग्रेस–शासन के दौरान हुई। 2011–12 से लेकर 2012–13 के बीच डिजिटल लेन–देन में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012–13 से लेकर 2013–14 के बीच डिजिटल लेन–देन में एक बार फिर 49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इन आंकड़ों को देखें तो प्रधानमंत्री जी के दावों की हवा निकल जाती है।

6- **<u>क्या कालाधन पकडा गया?</u>**

प्रधानमंत्री मोदी और वित्तमंत्री जेटली नवंबर, 2016 से मई, 2017 तक यह घोषणाएं करते रहे कि कुल 17,526 करोड़ रु. की 'छिपी हुई आय' (अनडिस्क्लोज़्ड इंकम) का पता लगाया गया। **वो यह बताना भूल गए कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के अंतिम दो सालों में 5 गुना ज्यादा कालाधन पकड़ा गया। (नीचे सारणी देखें)**

Year	**Black Money Detected (*in Rs Crores*)**
2012-13	29,630
2013-14	1,01,183
2014-15	23,108
2015-16	20,721
2016-17	29,211

यह सारणी साफ करती है कि कालाधन पकड़े जाने में कमी आई है।

यदि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया हर दावा झूठ साबित हो गया, तो भारत के 125 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री जी से निम्नलिखित प्रश्नों के जबाव चाहते हैं :–

1- बैंकों की कतारों में लगे लगभग 150 आम नागरिकों की मौत का जिम्मेदार कौन है?

2- आरबीआई द्वारा 135 बार नोटबंदी के नियमों में बदलाव करने से हुई अफरा–तफरी और नुकसान का जिम्मेदार कौन है?

3- नोटबंदी के चलते अकेले एमएसएमई सेक्टर में खत्म हुई 3.72 करोड़ से अधिक नौकरियों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?

4- करोड़ों घरेलू महिलाओं द्वारा बचाई गई जिंदगी भर की बचत का नुकसान करने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

5- छोटे दुकानदारों और छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के नोटबंदी की वजह से बंद हुए कारोबार की जिम्मेदारी किसकी है?

6- और सबसे बड़ी बात यह कि जीडीपी में 9.2 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत तक हुई गिरावट का जिम्मेदार कौन है, जिसकी वजह से देश को 3 लाख करोड़ रु. से ज्यादा का नुकसान हुआ?

नोटबंदी के बाद, जीएसटी से अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ी।

कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के साथ श्री पी. चिदंबरम, श्री जयराम रमेश, एआईसीसी महासचिव/प्रभारी तथा कांग्रेसशासित राज्यों के वित्तमंत्रियों ने जीएसटी बनाने, इसे लागू करने और दरों की खामियों के चलते मोदी सरकार द्वारा फैलाई गई अफरा तफरी का गहन विश्लेषण किया। इस अफरा–तफरी ने अतिलघु, लघु और मंझोले व्यापारों पर विराम लगा दिया तथा रुकी हुई अर्थव्यवस्था केचलते अनेकों नौकरियां खत्म हो गईं।

बैठक में इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई गई कि जीएसटी के अनुपालन ने अपने वर्तमान स्वरूप में दुकानदारों, काराबारियों तथा व्यापारियों को काम करना मुश्किल कर दिया है, जिससे उनकी जिंदगी भी की कमाई बर्बाद हो रही है। इसकी खामियों तथा घरेलू उपयोग के सामान पर ऊंची दरों ने गृहणियों तथा आम जनता का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। अनिश्चित मानसिकता की भ्रमित सरकार ने हर दिन नियमों में नए बदलाव करके व्यापारियों व आम नागरिकों की जिंदगी बहुत कठिन बना दी।

बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस नेतृत्व व कांग्रेस के वित्तमंत्री जीएसटी काउंसिल के अंदर व बाहर एमएसएमई, दुकानदारों, कारोबारियों, गृहणियों व आम जनमानस के कष्ट व पीड़ाओं को उठाएंगे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक केंद्र की भाजपा सरकार व्यापारियों और आम जनमानस की इन समस्याओं का समाधान नहीं कर देगी।